

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

Civil Writ Jurisdiction Case No.979 of 2018

=====

Gopal Shankar Singh, Son of Lakshmi Narayan Singh, Resident of Village-
Rampur, P.S.- Madhusudanpur, District- Bhagalpur.

.... Petitioner/s

Versus

1. The State of Bihar through the Principal Secretary, Department of Education, Government of Bihar, New Secretariat, Patna.
2. The Director, Primary Education, Department of Education, Government of Bihar, New Secretariat, Patna.
3. The Regional Deputy Director of Education (R.D.D.E.), Bhagalpur Division, Bhagalpur.
4. The District Education Officer, Bhagalpur-Cum-Chairman, District Primary Teachers Promotion Committee, Bhagalpur, District-Bhagalpur.
5. The District Programme Officer, (Establishment) Education Department, Bhagalpur-Cum-Member Secretary, District Primary Teachers Promotion Committee, Bhagalpur, District-Bhagalpur.

.... Respondent/s

=====

Appearance :

For the Petitioner/s : Mr. Ashok Kumar Choudhary, Advocate
Mr. Manoj Kumar Jha, Advocate

For the Respondent/s : Mr. S.K. Ranjan, AC to GP-17

=====

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE ANIL KUMAR UPADHYAY

ORAL JUDGMENT

Date: 20-04-2018

Heard learned counsel for the petitioner and the
learned counsel for the State.

2. The petitioner is aggrieved by the action on the part of the respondents in the matter of implementation of the decision of Regional Deputy Director of Education, Bhagalpur Division, Bhagalpur.

3. Mr. Ashok Kumar Choudhary, learned counsel for the petitioner has drawn the attention of the Court to the order passed by the R.D.D.E., Bhagalpur Division, Bhagalpur, contained in



Annexure-9. The Regional Deputy Director of Education, Bhagalpur Division, Bhagalpur, passed the order considering the decisions of the promotion Committee dated 20.11.2015.

4. The relevant part of the order contained in Annexure 9, reads as follows:

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं संचिका के समीक्षाक्रम में प्रधानाध्यापक पद पर दिनांक 20.11.2015 को प्रोन्नति समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में निर्गत प्रोन्नति आदेश में निम्नांकित त्रुटि उभरकर सामने आया:—

1..प्रोन्नति समिति के दो सदस्य, श्री दीपू कुमार, वरीय उपसमाहर्ता, एवं श्री एस0 के0 मेहरा, जिला लेखा पदाधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षक प्रोन्नति समिति, भागलपुर द्वारा प्रतिवेदित प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था0), शिक्षा विभाग, भागलपुर के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्गत प्रोन्नति आदेश ज्ञापांक 3076 दिनांक 01.12.2015 प्रोन्नति समिति के निर्णय के विरुद्ध है।

2.. वर्ष 2012 में जिला प्रारम्भिक शिक्षक प्रोन्नति समिति, भागलपुर द्वारा 280 प्रधानाध्यापकों को दिये गये प्रोन्नति में अपीलार्थी, श्री प्रवीण कुमार एवं श्री गोपाल शंकर सिंह को प्रोन्नति हेतु निर्गत प्रोन्नति आदेश ज्ञापांक 1003 दिनांक 30.03.2012 द्वारा प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति दिये जाने के पश्चात् पुनः प्रोन्नति आदेश ज्ञापांक 3076 दिनांक 01.12.2015 द्वारा दी गयी प्रोन्नति में वंचित रखा गया है।

3.. अपीलार्थी द्वारा स्नातकोत्तर की



योग्यतावर्द्धन नियुक्ति प्राधिकार की अनुमति से लिये जाने के उपरान्त भी प्रोन्नति से वंचित रखा गया है।

4.. प्रोन्नति नियमावली 2011 के प्रवृत्त होने के बाद पूर्व के निर्गत प्रोन्नति नियमावली 1993 एवं अन्य आदेश-निदेश निरसित माने गये हैं, फिर भी परिपत्र संख्या – 04 दिनांक 04.01.2010 का अनुपालन कर प्रोन्नति आदेश निर्गत किया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार अपील के निष्पादन हेतु निम्न आदेश दिया जाता है:—

1.. अपीलार्थी द्वारा प्रातःकालीन सत्र में स्नातकोत्तर की योग्यतावर्द्धन की गयी है व नियुक्ति प्राधिकार से अनुमति प्राप्त है एवं वर्ष 2012 में भी प्रोन्नति समिति द्वारा अपीलार्थी, श्री प्रवीण कुमार एवं श्री गोपाल शंकर सिंह को प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति दी गयी है। फलतः विभागीय परिपत्र संख्या 143 दिनांक 08.02.2013 के आलोक में एवं परिपत्र संख्या 592 दिनांक 10.05.2013 में निहित निदेश के सन्दर्भ में प्रोन्नति समिति के समक्ष रखते हुए नियमानुसार अर्हता प्राप्त अपीलार्थी को प्रोन्नति लाभ देने पर विचार किया जाय।

उपरोक्त आदेश के तहत अपीलवाद को निष्पादित किया जाता है, साथ ही यह निदेश दिया जाता है कि प्रोन्नति समिति के निर्णय से यथासमय अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अवगत कराया जाय।

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक,

भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर।

5. After the order of the Regional Deputy Director of



Education, Bhagalpur the Departmental Promotion Committee is required to consider the case of the petitioner but from the pleading, it appears that the direction of RDDE, Bhagalpur, contained in Annexure-9, was not acted upon.

6. Aggrieved by the inaction on the part of the respondents, the petitioner filed the present writ Application.

7. Learned counsel for the petitioner submits that in a system governed by rule of law, the order passed by the competent authority is required to be religiously followed by all concerned. Unfortunately, the authorities, who are obliged to implement the direction of the RDDE, Bhagalpur Division, Bhagalpur has not bothered to implement the direction of the R.D.D.E., Bhagalpur, and as a result of their inaction, the petitioner has been forced to file the present writ application.

8. Considering the aforesaid circumstance, the Court is constrained to issue direction to the RDDE, Bhagalpur Division, Bhagalpur to see that the order dated 29.04.2017 passed by the RDDE, Bhagalpur contained in Annexure-9, is implemented in its letter and spirit and all officers to whom the decision was required to implement may be saddled with appropriate action including the coercive action so that the officers may not dare to defy the direction of the superior officials. The RDDE, Bhagalpur is required to ensure



compliance of his own order dated 29.04.2017 in its letter and sprit preferably within a period of 60 days from the date of receipt/production of a copy of this order.

9. With the aforesaid, the writ application stands disposed of.

(Anil Kumar Upadhyay, J)

Uday/-

AFR/NAFR	NAFR
CAV DATE	NA
Uploading Date	24.04.2018
Transmission Date	

